खण्ड – 5 संख्या – 20

बिहार विधान–सभा वाद–वृत्त

सरकारी प्रतिवेदन

भाग –1

(कार्यवाही प्रश्नोत्तर)

वृहस्पतिवार, तिथि 18 सितम्बर, 1986 ई०

आगामी बैठक में विचारार्थ रखा जायेगा ।

3. उत्तर स्वीकारात्मक हैं ।

4. उपर्युक्त अनुशंसा पर केन्द्रीय क्रय समिति का अनुमोदन प्राप्त होने पर दवाओं को क्रय के सम्बन्ध में आगे की कार्रवाई की जायेगी ।

अधूरे भवन का निर्माण :

2809. **श्रीमती व्यूला दोजा :** क्या मंत्री, पशुपालन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

1. क्या यह बात सही है कि कटिहार जिला के बारसोई प्रखण्ड में बिछोर पंचायत में वर्ष 1972 में पशुचिकित्सालय भवन निर्माण का कार्य प्रारम्भ किय गया था ;

2. क्या यह बात सही है कि उक्त भवन निर्माण का कार्य वर्ष 1972 से ही अधूरा पड़ा है ;

3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो सरकार कबतक अधूरे भवन का निर्माण का कार्य पूरा कराने का विचार रखती है, यदि नहीं तो क्यों ?

श्री मदन प्रसाद सिंह : 1. उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है । उक्त पंचायत में पशुचिकित्सालय नहीं वरन् एक पशु चिकित्सालय उपकेन्द्र है ।

2. उत्तर स्वीकारात्मक है ।

3. इस पशुचिकित्सक उपकेन्द्र के भवन का निर्माण कार्य सामुदायिक विकास योजनान्तर्गत 50 प्रतिशत सरकारी अनुदान एवं 50 प्रतिशत जनता के अंशदान से पूरा कराया जाना था । चूँकि उक्त योजना अब कार्यरत नहीं है, इसलिये उक्त अधूरे निर्माण कार्य को राष्ट्रीय ग्रामीण नियोजन कार्यक्रम के अन्तर्गत पूरा कराने की कार्रवाई हेतु जिला पदाधिकारी कटिहार को लिखा जा रहा है ।

परियोजना कार्य का प्रारम्भ :

2814. **श्री शकील अहमद :** क्या मंत्री, सिंचाई विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

1. क्या यह बात सही है कि राज्य सरकार ने दिनांक 26-08-85 को निर्णय लिया कि विश्व बैंक की सहायता से वर्ष 1986 से प्रारम्भ होने वाली नलकूप परियोजना के कार्य की रूप रेखा एवं कार्य प्रणाली उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निर्धारित प्रणाली एवं रूप रेखा के आधार पर ही की जायेगी ;

2. क्या यह बात सही है कि उत्तर प्रदेश नलकूप परियोजना का कार्य यांत्रिक अभियंता संवर्ग द्वारा कराने तथा असैनिक अभियंता संवर्ग से अस्थायी रूप में सीमित अवधि के लिए गहन एवं प्रति नियुक्ति द्वारा कराने की नीति निर्धारित है, परन्तु बिहार सरकार ने उक्त संदर्भ में यांत्रिक अभियंता और पद सृजन एवं कार्य प्रणाली को अभी तक अस्पष्ट रखा गया है जिससे अनियमित ढंग से यांत्रिक अभियंताओं के बदले असैनिक अभियंताओं का पदस्थापन विभाग द्वारा किया जा रहा है ;